<u>रिपोर्टेबल</u>

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4384/2020

श्रीमती नीरज पत्नी रूपा राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 47, ग्राम सिंधपुरा, पोस्ट हिराणी वाया कुचामन, जिला नागौर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव के माध्यम से, शिक्षा विभाग, जयपुर

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर

3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

4. खंड विकास अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा विभाग, नोखा, जिला बीकानेर

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: सिस्को वेबएक्स ऐप के माध्यम से श्री भावित शर्मा

प्रतिवादी के लिए: श्री ऋषि सोनी, श्री पंकज के सहयोगी सिस्को वेबेक्स के माध्यम से शर्मा, एएजी अनुप्रयोग

आदेश

न्यायाधिपति दिनेश मेहता

दिनांकः 07/12/2020

1. वर्तमान मामले में जिस पहेली को हल करना आवश्यक है, वह यह है कि क्या एक उम्मीदवार, जिसने सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया है, राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 के तहत मातृत्व अवकाश का हकदार है?

2. इस तरह की कवायद शुरू करने से पहले, कुछ तारीखों पर ध्यान देना उचित होगा, जिनका मौजूदा मुद्दे पर प्रभाव पड़ता है:

(i) याचिकाकर्ता ने 15.05.2016 को एक बच्चे को जन्म दिया;

(ii) याचिकाकर्ता को 04.06.2016 को फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पीटीआई), ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति दी गई थी;

(iii) याचिकाकर्ता ने 06.06.2016 को अपनी ज्वाइनिंग दी;

(iv) याचिकाकर्ता ने 21.06.2016 को मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था;

(v) याचिकाकर्ता 26.06.2016 से 10.11.2016 (142 दिन) तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई,

(vi) मातृत्व अवकाश के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर दिनांक 13.08.2018 और 17.07.2019 के आदेश के माध्यम से निर्णय लिया गया था;

(vii) याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि 26.09.2018 से की गई (आदेश दिनांक 21.11.2019 के माध्यम से);

(viii) रिट याचिका 19.05.2020 को दायर की गई।

3. याचिकाकर्ता, जिसे दिनांक 04.06.2016 के नियुक्ति आदेश के तहत फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था, ने नियुक्ति आदेश प्राप्त होने से कुछ दिन पहले 15.05.2016 को एक बच्चे को जन्म दिया।

4. चूँकि याचिकाकर्ता को सिजेरियन सेक्शन से गुजरना पड़ा था, वह शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं थी, लेकिन ज्वाइन न करने के प्रतिकूल परिणाम से बचने के लिए, उसने 06.06.2016 को अपनी ज्वाइनिंग देना पसंद किया।

5. अपने बच्चे और खुद की देखभाल के उद्देश्य से, उसने 21.06.2016 को मातृत्व अवकाश के अनुदान के लिए एक आवेदन दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उसने 15.05.2016 को सिजेरियन सेक्शन द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया है और इस प्रकार, वह ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो पाएंगी। याचिकाकर्ता ने दायर आवेदन

के साथ जन्म प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए थे।

6. 142 दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद 10.11.2016 को याचिकाकर्ता वापस ड्यूटी पर आयी।

7. याचिकाकर्ता के उपरोक्त अवकाश आवेदन (21.06.2016 को दायर) को उत्तरदाताओं द्वारा सबसे पहले 13.08.2018 के संचार के माध्यम से निपटाया गया, जिसके तहत अवैतनिक 90 दिनों की अवकाश स्वीकृत की गई।

8. एक अन्य संचार दिनांक 17.07.2019 द्वारा, याचिकाकर्ता को कुल 142 दिनों की अवकाश स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 90 दिनों को दिनांक 13.08.2018 के संचार के अनुसार अवैतनिक अवकाश के रूप में माना गया था और 52 दिनों के अवैतनिक अवकाश (ईओएल) को असाधारण अवकाश के रूप में माना गया था।

9. दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि को 112 दिन बढ़ा दिया और दिनांक 21.11.2019 के आदेश के माध्यम से 26.09.2018 से उसकी सेवाओं की पुष्टि की।

10. याचिकाकर्ता ने एक शिकायत के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता की पुष्टि को 112 दिनों

की अवधि के लिए स्थगित करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी पुष्टि 05.06.2018 से प्रभावी होनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश से इनकार करने वाले आदेश को भी सवालों के घेरे में बताया है।

11. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री भवित शर्मा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की पुष्टि को 112 दिनों तक स्थगित करना उत्तरदाताओं के लिए उचित नहीं था, जबकि याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश न देने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई मनमानी और आरएसआर का नियम 103 के विपरीत है।

12. उन्होंने तर्क दिया कि आदेश दिनांक 21.11.2019 इसलिए प्रतिवादियों की मातृत्व अवकाश स्वीकृत न करने की कार्रवाई भी रद्द करने और अलग रखे जाने योग्य है।

13. विद्वान वकील ने हर्षिता यादव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य; मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 19.05.2017 के फैसले पर भरोसा किया। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11833/2014 में कहा गया कि याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश की हकदार है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने सरकारी सेवा में प्रवेश करने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया था।

14. श्री ऋषि सोनी, श्री पंकज शर्मा, एएजी के सहयोगी, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील - राज्य ने प्रारंभिक आपत्ति विलम्ब के संबंध में उठाई है।

15. इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि याचिकाकर्ता के मातृत्व अवकाश के आवेदन पर दिनांक 13.08.2018 और 17.07.2019 के आदेशों के तहत विचार किया गया था, उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने लगभग एक वर्ष की देरी के बाद मई, 2020 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इस प्रकार, न्यायसंगत राहत की मांग करने वाली उसकी रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

16. उपरोक्त प्रारंभिक आपत्ति के अलावा, एक तर्क दिया गया था कि हर्षिता यादव के मामले (उक्त) में इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय बाध्यकारी नहीं है, मातृत्व अवकाश को नियंत्रित करने वाले आरएसआर के नियम 103 के बुनियादी प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर्षिता यादव का फैसला पूरी तरह से मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (इसके बाद "1961 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों पर निर्भर करता है और आरएसआर के प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है।

17. आरएसआर के नियम 103 के प्रावधानों को उत्साहपूर्वक पढ़ते हुए, श्री सोनी ने प्रस्तुत किया कि मातृत्व अवकाश केवल उस मामले में

स्वीकार्य है, जहां एक महिला के सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों में शामिल होने के बाद बच्चे का जन्म होता है। नियम 103 की प्रारंभिक पंक्ति में "एक सरकारी कर्मचारी के लिए" अभिव्यक्ति के उपयोग पर अधिक जोर देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे को जन्म देने की तारीख (15.05.2016 को) याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी नहीं थी और इसलिए, उसे मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता। इसे अलग तरह से कहें तो उनका तर्क यह था कि चूंकि याचिकाकर्ता का बच्चा सरकारी सेवाओं में शामिल होने से पहले पैदा हुआ था, इसलिए वह नियमों के तहत मातृत्व अवकाश का दावा नहीं कर सकती।

18. यह प्रस्तुत किया गया कि यदि याचिकाकर्ता को सलाह दी जाती, तो वह जल्दबाजी में शामिल होने और मातृत्व अवकाश का दावा करने के बजाय आकस्मिक स्थिति के मद्देनजर ज्वाइनिंग के विस्तार के लिए आवेदन कर सकती थी।

19. श्री सोनी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 04.05.2017 के फैसले पर भरोसा किया, जो स्वीटी देवी बनाम पं.बी.डी.शर्मा, स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के मामले में दिया गया था; एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9385/2017 और प्रार्थना की कि इस फैसले के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

20. सुना गया।

21. याचिकाकर्ता द्वारा मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करने की तारीख पर मौजूद आरएसआर के नियम 103 के प्रावधानों का अध्ययन करना लाभदायक होगा। इसे इन्फ्रा के रूप में भी पढ़ा जाता है:-

> "103:- दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को इसके प्रारंभ होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि तक मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। हालाँकि, यदि दो बार इसका लाभ उठाने के बाद भी कोई जीवित बच्चा नहीं है, तो मातृत्व अवकाश एक और अवसर पर दिया जा सकता है।
>
> ऐसी अवधि के दौरान, वह अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन पाने की हकदार होगी। ऐसी अवकाश को अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा बल्कि ऐसी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में अलग से की जानी चाहिए।
>
> * जोर दिया गया।

22. इस लाभकारी प्रावधान को उस कर्मचारी को सक्षम करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है जो एक बच्चे की मां है, ताकि वह प्रसव के बाद की समस्याओं से उबर सके और उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सके, ताकि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के

आदेश का पालन किया जा सके।

23. हालांकि सीधे तौर पर यह मुद्दा नहीं है, लेकिन पितृत्व अवकाश के संबंध में कुछ हद तक समान प्रावधान भी विवाद के संदर्भ में संदर्भ की मांग करते हैं। आरएसआर का नियम 103 ए इस प्रकार है:-

> "103 ए: पितृत्व अवकाश: दो से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष सरकारी कर्मचारी को उसकी पत्नी के प्रसूति के दौरान 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश (अधिकतम दो बार) दिया जा सकता है, यानी बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले से तीन महीने बाद तक; और यदि इस अवधि के भीतर ऐसी अवकाश का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे व्यपगत माना जाएगा।
>
> ऐसी अवकाश की अवधि के दौरान, सरकारी कर्मचारी को अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। पितृत्व अवकाश को अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में अलग से की जानी चाहिए और इसे किसी अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है (जैसा कि मातृत्व अवकाश के मामले में)

सरकारी कर्मचारी की पत्नी के गर्भपात सहित गर्भपात के मामले में ऐसी अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

24. आरएसआर के नियम 103 पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि यह कर्मचारी केंद्रित है। इसका बच्चे के जन्म की तारीख या घटना से कोई संबंध या संबंध नहीं है। यह नियम दो से कम बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने का अधिकार देता है। इस तरह के लाभ के लिए आवश्यक शर्तें हैं- (i) एक महिला सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए और (ii) उसके दो से कम जीवित बच्चे होने चाहिए।

25. इसके विपरीत, यदि नियमों के नियम 103ए (जो पितृत्व अवकाश से संबंधित है) में निहित अनुरूप प्रावधान पर ध्यान दिया जाता है, कोई यह पाएगा कि पितृत्व अवकाश को बच्चे के जन्म और पत्नी के प्रसूति के साथ जोड़ा गया है या इसका सीधा संबंध दिया गया है। एक पिता कारावास की अवधि के दौरान यानी बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले से 3 महीने बाद तक ऐसी अवकाश का लाभ उठा सकता है। यदि इस तरह की अवकाश का लाभ नहीं उठाया गया है, तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है, यह नियमों के नियम 103ए का आदेश है।

26. नियम 103 और नियम 103ए का तुलनात्मक और संयुक्त अध्ययन विधायी मंशा को स्पष्ट करता है। एक महिला सरकारी

कर्मचारी या मां बच्चे के जन्म की तारीख की परवाह किए बिना निर्धारित अवधि के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है; जबकि एक पुरुष सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी के कारावास के दौरान 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश का लाभ उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, पितृत्व अवकाश के मामले में बच्चे के जन्म की तारीख महत्वपूर्ण है, जबकि मातृत्व अवकाश के मामले में इसकी अधिक प्रासंगिकता नहीं है।

27. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, अभिव्यक्ति का उपयोग - "इसके प्रारंभ होने की तिथि से"। ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग भी मौजूदा मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उल्लेखनीय है कि इन नियमों को शामिल करने की तिथि यानी 06.12.2004 को विधायिका ने ऐसी पात्रता तुरंत प्रदान करना उचित समझा था। दूसरे शब्दों में, नियम बनाने वाले प्राधिकारी का इरादा उन सभी कर्मचारियों को ऐसा लाभ प्रदान करना था, जिन्होंने पहले ही ऐसी तारीख (06.12.2004) को एक बच्चे को जन्म दिया था, इसीलिए ऐसी शर्त (इसके प्रारंभ होने की तारीख से) बनाई गई थी, डिलीवरी की घटना का कोई संदर्भ दिए बिना।

28. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चूंकि इन नियमों की घोषणा की तिथि पर, एक कर्मचारी, जिसने पहले ही बच्चे को जन्म दिया था,

मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने का हकदार था, किसी कर्मचारी को बाहर करना न केवल अन्यायपूर्ण होगा, बल्कि भेदभावपूर्ण भी होगा। जिन्होंने सरकारी सेवा में आने से कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मूल पद पर नियुक्ति के बाद, एक पदधारी सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सरकारी सेवक बन जाता है और एक माँ की मातृत्व आवश्यकताओं को केवल इसलिए ग्रहण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह कर्तव्यों में शामिल हो गई है।

29. नियम 103 जन्मतिथि के आधार पर अधिकार सृजित या प्रदत्त नहीं करता। इसमें बस यह प्रावधान है कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश इसके प्रारंभ होने की तारीख से दिया जा सकता है। इसलिए, इस तरह की अवकाश के लिए आवेदन करने की तिथि पर, यदि किसी महिला कर्मचारी को प्रसव संबंधी जरूरतों और बच्चे के पालन-पोषण या देखभाल के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है, तो इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

30. यह तर्क देकर 'छद्म भेद' निकालना कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं था, बच्चे का जन्म कब हुआ या दूसरे शब्दों में बच्चे का जन्म शामिल होने से पहले हुआ, यह नियम 103 के प्रावधानों के

विपरीत है और नियम के मूल उद्देश्य के साथ सीधे टकराव में है। ऐसा रुख मनमाना और असमान है, यदि नहीं तो अमानवीय भी।

31. ऐसी स्थिति होने के कारण, यह न्यायालय उत्तरदाताओं के तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ है, जिसे प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील श्री सोनी ने जोर-शोर से आगे बढ़ाया है।

32. देरी और विलंब के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को लगता है कि सबसे पहले यह राज्य के लिए उपलब्ध नहीं है और यह पाता है कि मौजूदा तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में इसे खारिज किया जा सकता है।

33. निर्विवाद रूप से, 21.06.2016 को दायर याचिकाकर्ता का अवकाश आवेदन लगभग दो वर्षों तक अप्राप्य/अनसुना रहा। अंततः उत्तरदाताओं द्वारा दिनांक 13.08.2018 और 17.07.2019 के आदेश से इसका निपटारा किया गया - याचिकाकर्ता की अवकाश स्वीकृत की गई, लेकिन बिना वेतन के।

34. इसे छोड़कर, 21.11.2019 को पारित एक आदेश के माध्यम से, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की पुष्टि को 112 दिनों की अवधि के लिए स्थगित कर दिया।

35. ऐसी स्थिति का सामना करने पर याचिकाकर्ता कानूनी सहारा लेने के लिए बाध्य हुआ।

36. ऐसी तारीख यानी 21.11.2019 से गिनती करते हुए, तत्काल रिट याचिका, जो 19.05.2020 को दायर की गई है, को किसी भी तर्क से विलंबित नहीं माना जा सकता है।

37. ऊपर जो भी कहा गया है, उसके बावजूद, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, राज्य ऐसा तकनीकी बचाव नहीं ले सकता है, खासकर जब कोई पीड़ित पक्ष उचित अवधि के भीतर यानी कार्रवाई के कारण के तीन साल के भीतर अदालत में पहुंचता है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता की निष्क्रियता के कारण किसी तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल नहीं हैं और/या अन्य कर्मचारी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हैं। देरी के आधार पर किसी याचिका का विरोध करते समय, राज्य को यह भी दावा करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता की लंबे समय तक निष्क्रियता के कारण, मुद्दे को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक सामग्री/सबूत नष्ट हो गए हैं/समाप्त हो गए हैं या उसके पास उपलब्ध नहीं हैं।

38. निस्संदेह, वर्तमान कारण न तो चिंता का विषय है और न ही किसी भी तरह से किसी अन्य कर्मचारी के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसलिए, जैसा कि उत्तरदाताओं ने अनुरोध किया है, याचिकाकर्ता के चेहरे पर न्याय के दरवाजे बंद नहीं किये जा सकते।

39. मामले की तथ्यात्मक स्थिति न्यायालयों द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की याद दिलाती है:-

(ए) कालूराम सीताराम बनाम के मामले में। भारत का प्रभुत्व (एआईआर 1954 बॉम्बे 50), एक व्यक्तिगत नागरिक और राज्य के बीच मामले का फैसला करते समय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

> "अब, हमें अक्सर यह कहने का अवसर मिला है कि जब राज्य किसी नागरिक के साथ व्यवहार करता है, तो उसे आमतौर पर तकनीकियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और यदि राज्य संतुष्ट है कि नागरिक का मामला न्यायसंगत है, भले ही कानूनी बचाव उसके लिए खुला हो, तो उसे एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए, जैसा कि प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने कहा है।"

(बी) इसके अलावा, पोर्ट ट्रस्ट बनाम ह्यमांशु इंटरनेशनल के मामले में: (1979) 4 एससीसी 176, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

> "2...इस धारा पर आधारित परिसीमा की दलील वह है जिसे अदालत हमेशा नापसंदगी की दृष्टि से देखती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पोर्ट ट्रस्ट जैसे सार्वजनिक

प्राधिकरण को पूरी नैतिकता और न्याय के तहत नागरिक के उचित दावे को विफल करने के लिए ऐसी याचिका उठानी चाहिए। अब समय आ गया है कि सरकारें और सार्वजनिक प्राधिकरण नागरिकों के वैध दावों को विफल करने के उद्देश्य से तकनीकी दलीलों पर भरोसा न करने की प्रथा अपनाएं और वही करें जो नागरिकों के लिए उचित और उचित हो। निःसंदेह, यदि कोई सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण कोई तकनीकी याचिका उठाता है, तो न्यायालय को उस पर निर्णय लेना होगा और यदि याचिका उचित है, इसे अदालत द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसी याचिका आम तौर पर किसी सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नहीं ली जानी चाहिए, जब तक कि दावा उचित न हो और इसे दाखिल करने में देरी न हो। , ऐसे दावे का विरोध करने के उद्देश्य से साक्ष्य अनुपलब्ध हो गए हैं..."

40. इस तरह का तर्क उठाने से पहले, उत्तरदाताओं को बेहतर ढंग से अपनी कार्रवाई का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था और सभी संबंधितों के सामने एक प्रश्न रखना चाहिए था कि याचिकाकर्ता के मातृत्व

अवकाश (दिनांक 21.06.2016) के अनुदान के आवेदन का दो साल तक जवाब क्यों नहीं दिया गया?

41. याचिकाकर्ता की तथाकथित निष्क्रियता पर उंगली उठाना उत्तरदाताओं (जिन्हें स्वयं एक आवेदन पर निर्णय लेने में दो साल लग गए, वह भी बेदर्दी से) को शोभा नहीं देता, जबकि वे स्वयं दोषी हैं। इस प्रकार, प्रारंभिक आपत्ति योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

42. इस न्यायालय का मानना है कि अब समय आ गया है जब राज्य को मामले की योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बेकार की आपत्तियों या देरी की बजाय एक नागरिक को अधिकारों या लाभों की अनुमति तक ही सीमित रखना चाहिए।

43. अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, प्रतिद्वंद्वी वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विस्तार से विचार करना इस न्यायालय के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले, हर्षिता यादव के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर गौर करना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है: -

> "तर्क के दौरान, इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि कर्मचारी को वेतन और अन्य मौद्रिक लाभ देना और सेवा में शामिल होना पूरी तरह से अलग है। याचिकाकर्ता, वास्तव में, 08.11.2011 को सरकारी सेवा

में शामिल हुआ था। उस वक्त वह आठ दिन के बच्चे की मां थीं. याचिकाकर्ता नवंबर, 2011 के महीने में अवकाश पर चला गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 एक लाभकारी कानून है। राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि नवजात शिशु देश का भविष्य है और उसका न केवल अच्छे से पालन-पोषण हो, बल्कि वह एक स्वस्थ बच्चे के रूप में विकसित हो। विद्वान सरकारी वकील श्री संजय शर्मा को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस दावे से कोई आपत्ति नहीं है कि आठ दिन के बच्चे को माँ द्वारा देखभाल, ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। श्री संजय शर्मा ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि राज्य सरकार मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों से बंधी है और उन्होंने राज्य सरकार के नियमों में मातृत्व अवकाश देने का भी प्रावधान किया है। हालाँकि, यह अदालत इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं रह सकती कि याचिकाकर्ता ने न्यूनतम 80 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बारह महीनों से पहले के दिन. यह एक ऐसा मामला है जहां इस अदालत को इक्विटी को संतुलित करना चाहिए।

इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि 09.11.2011 से 27.04.2012 तक की अवधि को देय अवकाश माना जाएगा और उक्त अवधि के लिए याचिकाकर्ता को कोई वेतन या भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन उक्त अवधि वही मानी जाएगी जिस दिन याचिकाकर्ता ड्यूटी पर था। इस प्रकार, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता की सेवाओं को 08.11.2011 से माना जाएगा।"

44. यह सच है कि हर्षिता यादव के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय 1961 के अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित है और आरएसआर के नियम 103 को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। लेकिन केवल यह तथ्य कि हर्षिता यादव (सुप्रा) के मामले में नियम 103 का उल्लेख नहीं किया गया है, उक्त निर्णय को गलत नहीं ठहराता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय ने अब आरएसआर के नियम 103 के संबंध में उत्तरदाताओं के तर्क पर विचार किया है और निपटाया है, उत्तरदाताओं की कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

45. स्वीटी देवी के मामले (सुप्रा) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर आगे बढ़ते हुए, यह देखना पर्याप्त है कि

वर्तमान मामले पर इसका कोई आवेदन नहीं है। क्योंकि, पंजाब सेवा नियमों में संबंधित नियम स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। स्वीटी देवी के मामले (सुप्रा) के फैसले में संदर्भित पंजाब सेवा नियमों के पैरा 8.127 (ए) को पुनः प्रस्तुत करना अप्रासंगिक नहीं होगा:

> "8.127 (ए) नियम 8.23 के तहत सक्षम प्राधिकारी एक महिला सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर मातृत्व अवकाश दे सकता है और ऐसी अवकाश का अनुदान इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि कारावास की तारीख इस अवकाश की अवधि के भीतर आती है और इस प्रकार दी गई अवकाश महिला सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते से डेबिट नहीं की जाएगी:
>
> बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत कोई भी अवकाश उस महिला सरकारी कर्मचारी को नहीं दी जाएगी जिसके तीन या अधिक जीवित बच्चे हैं।

46. मातृत्व अवकाश के लाभ से इनकार करते समय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि कारावास की तारीख याचिकाकर्ता के शामिल होने से पहले की तारीख थी, इसलिए

याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश का दावा नहीं कर सकती। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जन्म तिथि को कारावास की तिथि माना है; जो इस न्यायालय की राय में, उचित सम्मान के साथ, एक सही स्थिति और उचित व्याख्या नहीं है। प्रसूति को बच्चे के जन्म या प्रसव की तारीख के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कारावास की तारीख आरएसआर के नियम 103 में प्रयुक्त एक अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए, यह न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा खींची गई रेखा को तोड़ने के लिए राजी नहीं है, खासकर जब पंजाब नियमों और विचाराधीन नियमों के प्रावधानों के बीच स्पष्ट और स्पष्ट अंतर है।

47. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह न्यायालय एक अपरिवर्तनीय निष्कर्ष पर पहुंचता है कि याचिकाकर्ता आरएसआर के नियम 103 के संदर्भ में मातृत्व अवकाश देने का हकदार है, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने सरकारी सेवा में आने से पहले ही बच्चे को जन्म दिया था।

48. दिनांक 13.08.2018;17.07.2019;और 21.11.2019 के विवादित आदेश, इस प्रकार, योग्य हैं और इन्हें रद्द किया जाता है।

49. याचिकाकर्ता की स्वीकृत 142 दिनों की अवकाश को मातृत्व अवकाश माना जाएगा।

50. एक आवश्यक परिणाम के रूप में, याचिकाकर्ता आरएसआर के नियम 103 के अनुसार, ऐसी अवकाश की अवधि के लिए वेतन का हकदार होगा और 05.06.2018 से पुष्टि की जाएगी।(उसके शामिल होने की तारीख से दो साल की सेवा पूरी होने पर)।

51. परिणाम का पालन आज से तीन महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है।

52. प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से, आरएसआर के नियम 103 और 103 ए को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह घोषित किया जाता है कि एक महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की हकदार है। यदि वह प्रसूति की अवधि के भीतर, यानी बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले से तीन महीने बाद तक शामिल होती है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि बच्चे का जन्म नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले या शामिल होने से पहले हुआ था।

53. याचिका स्वीकृत की जाती है। लागत आसान हो गई।

54. स्थगन आवेदन भी निस्तारित होता है।

(न्यायाधिपति दिनेश मेहता)

(अनुवाद एआई टूल SUVAS के माध्यम से अनुवादक की मदद से किया गया है)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय का उपयोग वादी को अपनी भाषा में समझने के लिए सीमित उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।